DSSSB TGT & PGT

Part-B

SCHOLAR BATCH

INDIAN ECONOMY

Poverty

Part -7

LIVE 09-07-2024 08:00 PM

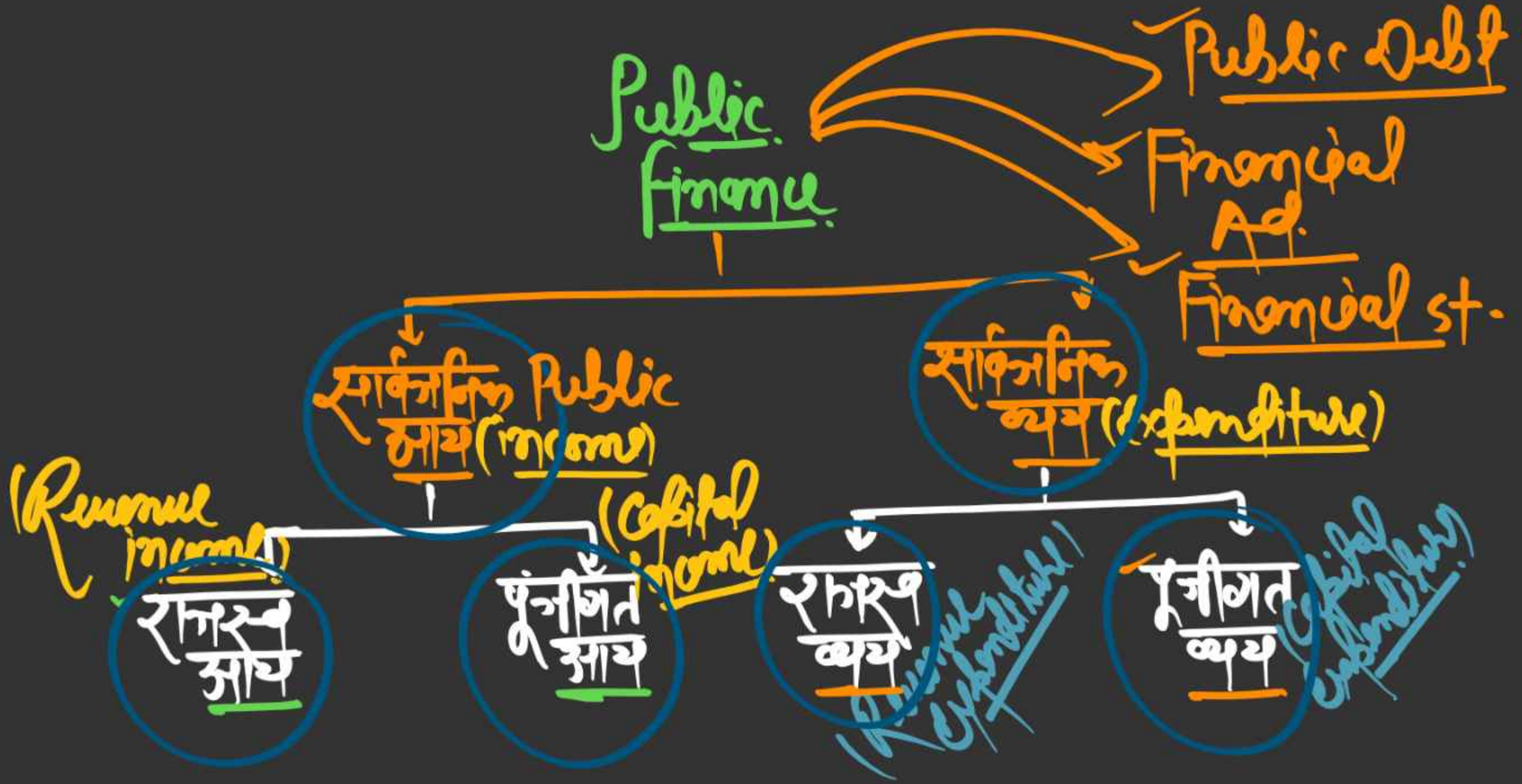
Public Finance
Public Debt
Financial Aid
Financial st.
सार्वजनिक आय (Income)
सार्वजनिक व्यय (Expenditure)
(Revenue Income)
(Capital Income)
राजस्व आय
पूंजीगत आय
राजस्व व्यय
पूंजीगत व्यय

संघवाद

शासन का स्तर से अधिक स्तर पर होना।

केन्द्र सरकार

राज्य सरकार

स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ

लोक वित्त

लोक वित्त का अर्थ :-

⇒ राज्य अपने दायित्वों को सार्वजनिक सत्ताओं (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन संस्थाओं आदि) के माध्यम से वित्तीय साधनों (धन) के द्वारा सम्पन्न करती हैं। इन्हीं संस्थाओं के वित्त से सम्बंधित सिद्धान्तों, समस्याओं एवं नीतियों के विधिवत् अध्ययन को ही लोकवित्त (Public Finance) कहा जाता है।

⇒ लोकवित्त मात्र सरकारी आय-व्यय की अवधारणाओं से सम्बंधित नहीं है, बल्कि इसके आयाम कहीं अधिक विस्तृत है। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति आदि भी शामिल होते हैं।

लोकवित्त का विभाजन :-

⇒ लोकवित्त को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया जाता है।

1) सार्वजनिक आय (Public Income)
   - राजस्व आय
   - पूँजीगत आय
2) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)
   - राजस्व व्यय
   - पूँजीगत व्यय
3) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)
4) वित्तीय प्रशासन (Financial Administration)
5) आर्थिक स्थिरता (Economical stability)
   - राजकोषीय नीति

सार्वजनिक आय

सार्वजनिक आय से आशय सरकार को किसी एक वर्ष में विविध स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से है। सार्वजनिक आय के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं।

① राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Income)

② पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital income)

Digvijay singh GS

① राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Income) :-

⇒ ऐसी सार्वजनिक प्राप्तियाँ, जिनसे न तो सरकार की देयता में वृद्धि होती है, और न ही सरकार की परिसम्पत्तियों में कमी आती है।
- ↳ सरकार की देनदारी नहीं
- ↳ सरकार की आर्थिक क्रिया का प्रतिफल नहीं माना जाता है।

⇒ राजस्व प्राप्तियाँ दो प्रकार की हैं।
- i) कर आय (Tax Revenue)
- ii) गैर-कर आय (Non Tax Revenue) → लाभांश

② पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Income):-

⇒ ऐसी प्राप्तियाँ, जिनके बदले में सरकार को भुगतान करना पड़ता है, पूँजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं। यह भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाता है।
- ↳ सरकार की देयता में वृद्धि
- ↳ आर्थिक क्रिया का प्रतिफल माना जाता है।

⇒ विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्य सरकारों से वापस प्राप्त ऋण व भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त धनराशि इसकी मुख्य मदें हैं।

- Direct Tax (सम्पत्ति कर)
  - Income Tax
  - Corporate Tax
  - Gift Tax
- Indirect Tax
  - GST
  - Sales Tax
  - Custom Duty

सार्वजनिक व्यय

⇒ सार्वजनिक व्यय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किये जाने वाले व्यय को कहते हैं।

⇒ सरकारी व्यय उन व्ययों का सूचक होता है, जोकि सरकारी प्रशासन अर्थात् केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा अपने नागरिकों की रक्षा करने एवं अनेक आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण हेतु किए जाते हैं।

⇒ सार्वजनिक व्यय के अन्तर्गत योजनागत व्यय एवं गैर-योजनागत व्यय को सम्मिलित किया जाता है।

⇒ योजनागत व्यय विकासशील प्रकृति का होता है तथा आने वाले समय में वह सार्वजनिक आय को बढ़ाने में सहायक होता है।

⇒ गैर-योजनागत व्यय गैर-विकासशील प्रकार का होता है। जैसे - रक्षा व्यय, ब्याज, सब्सिडी, प्रशासनिक व्यय इत्यादि।

⇒ सार्वजनिक व्यय दो प्रकार के होते हैं।
- i) राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)
- ii) पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

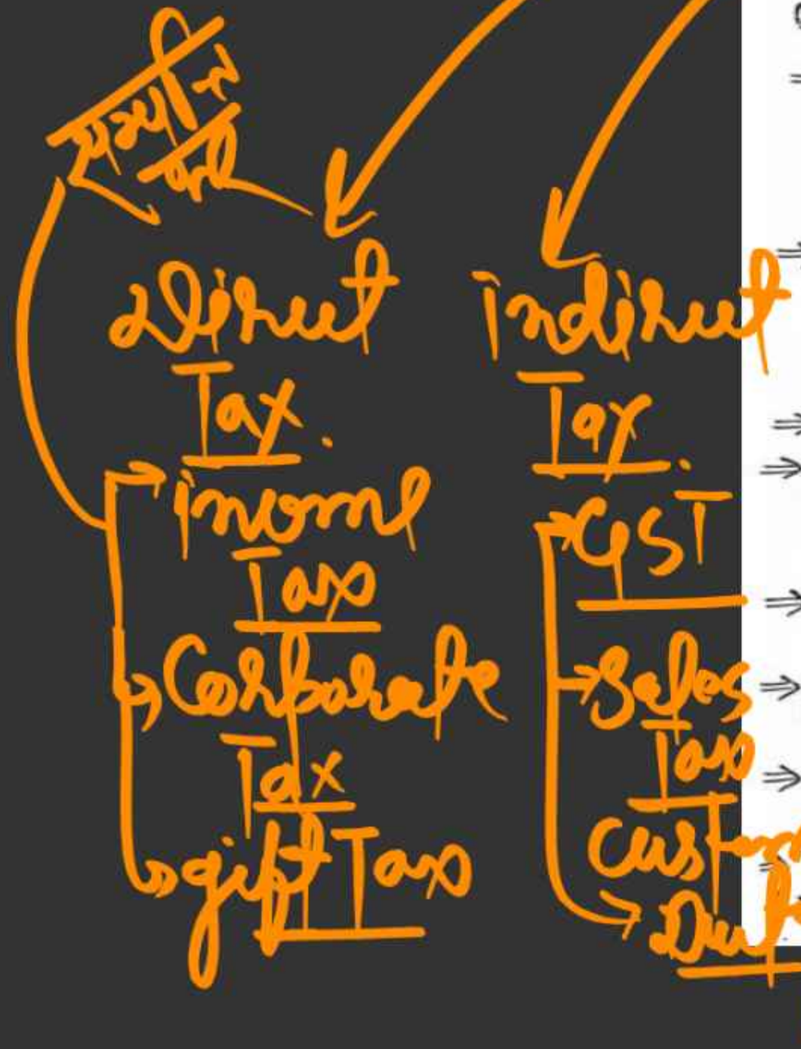

① राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) :-

⇒ साधारणतः राजस्व व्यय सार्वजनिक व्यय का वह स्वरूप है, जिससे किसी भी उत्पादित कोटि की परिसम्पत्ति का सृजन नहीं होता है।

⇒ राजस्व व्यय का सम्बंध चालू खाते से होता है। सामान्यतः राजस्व व्यय की प्रमुख मदें हैं – सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय, सरकारी सब्सिडी तथा ब्याज अदायगी एवं अनुदान।

② पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) :-

⇒ ऐसे व्यय जिनसे सरकार की परिसम्पत्तियों में वृद्धि होती है। पूँजीगत व्यय उत्पादक कोटि का होता है। इसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहता है। जैसे – आधारिक संरचना का निर्माण करवाना, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदत ऋण और अग्रिम पूँजीगत व्यय भी प्रमुख मदे हैं।

Deficit (घाटा)

Digvijay Singh IAS